State	Sugarcane 1994-95	Production 1995-96 (Advance Estimate)
15. Tamil Nadu	352.36	284.00
16. Uttar Prades	1099.07	1128.39
17. West Bengal	6.49	10.52
18. Others	5.50	5.50
ALL INDIA	2712.28	2673.84

Opening of Wagah Border Route for Indo-Pak Trade

80. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are considering the opening of Wagah border route for Indo-Pak trade;

(b) whether Government would consider making the Wagah route opening conditional on Pakistan agreeing to open the Gadro route on Rajasthan-Sindh border, for trade and traffic; and

(c) if not, the reason therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) and (b) Requests received from Indian trade and industry for opening up of Wagah border for overland trade with Pakistan are being looked into but no decision has been taken thereon so far. As regards opening up of the Gadro route, a communication on the subject had been sent to Pakistan in January 1995 proposing bilateral discussions which has not been responded to from the Pakistani side.

(c) Does not arise.

नियंत्रित दरों पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराया जाना

132. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अधिकृत दुकानों के माध्यम से केवल गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को नियंत्रित दरों पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना से मध्यम वर्ग, विशेष रूप से निम्न मध्यम वर्ग के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनकी आर्थिक स्थिति का संतुलन नहीं बिगड़ जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में असंतुलनों को दूर करने के लिए क्या योजना बनाने का विचार रखती है और उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य सर्व-सुलभ हकदारी के आधार पर छः आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल तथा साफ्ट कोक की आसानी से चुकाए जा सकने वाले मूल्यों पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर दुकानों के जरिए अन्य उपभोक्ता वस्तुओं को देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।